

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
देहरादून ।

न्याय अनुभाग : 1

देहरादून : दिनांक : 17 फरवरी, 2007

विषय: मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सृजित पदों की निरन्तरता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 6-एक(5)/XXXVI(1)/2006-184/01-टी0सी0-1 दिनांक 18 फरवरी, 2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु मूल रूप में शासनादेश संख्या- 106-एक/न्याय विभाग/2002, दिनांक 1-5-2002 द्वारा सृजित 23 पदों, मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति हेतु, शासनादेश संख्या- 12-एक(5)/न्याय विभाग/2003, दिनांक 21-8-2003, द्वारा सृजित 02 पदों, जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या- 15-एक (5)/न्याय विभाग/2003, दिनांक 25-7-2003द्वारा सृजित कुल 06 पदों, जनपद उधमसिंह नगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या- 16-एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 20-8-2003 द्वारा सृजित 02 पदों, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या- 5-एक(5)/छत्तीस (1)/न्या0अनु0/2005 दिनांक 11-2-2005 द्वारा सृजित 01 पद एवं शासनादेश संख्या 8-एक (5)/न्याय विभाग /2003 दिनांक 28-6-2005 द्वारा सृजित 02 पदों अर्थात् कुल 36 पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, दिनांक 1-3-2007 से 29-2-2008 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त के साथ इस हेतु स्वीकृत कार्यालय व्यय के अनुदान की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. उक्त प्राधिकरणों एवं समिति के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी ।

3. उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 04 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिये लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-00" के अन्तर्गत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिये लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 संपादित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92, दिनांक 7-11-92, (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त), द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या- 36(1)/XXXVI(1)-एक/07-184/01टी0सी0-1 तदुदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवम् हकदारी) उत्तराखण्ड, मांजरा, देहरादून ।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 3- जनपद न्यायाधीश बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवम् उधमसिंहनगर ।
- 5- वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,